

प्रश्न सं. [क. 3293]

पारिशिष्ट - 1
परिशिष्ट - 1

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दमोह

क्रमांक / खनिज / 2019 / 215

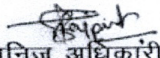
दमोह, दि 01/3/7/19

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म0प्र0रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लि0,
सागर म0प्र0विषय- दमोह विधानसभा अन्तर्गत ग्राम जमुनिया में अवैध उत्खनन के संबंध में ।
संदर्भ - आपका पत्र क्र0 388 / एमपीआरडीसी वि0स0 / मा0स0 / 2019-20 सागर दिनांक 4 / 7 / 2019
एव -00-

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र के विधानसभा तारकित प्रश्न क्र0 3293 द्वारा श्री राहुल सिंह के संबंध में जानकारी चाही गई है जो बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या भीलमपुर से बालाकोट सड़क निर्माण का ठेका दिलीप विल्डिकॉन कंपनी को दिया गया था उक्त सड़क में उपयोग के लिए कोई मुरम की खदान स्वीकृत है, यदि हाँ तो कहां और कौन से विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई ?	भीलमपुर से बालाकोट सड़क निर्माण का ठेका दिलीप विल्डिकॉन कंपनी को दिया जाना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है । कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार उक्त सड़क के उपयोग के लिए कोई मुरम की खदान स्वीकृत नहीं है । शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नहीं उठता ।
(ख)	प्रश्न (क) अनुसार क्या वर्ष 1999 में काले पत्थर के उत्खनन के लिए उक्त अधिकारियों द्वारा बिना उच्चतम न्यायालय की गार्ड लाईन फालो करते हुये प्राइवेट कम्पनी को लीज स्वीकृत कर दी । याचिकाकर्ता के द्वारा मामला एन0जी0टी0के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया । जिसमें कोर्ट के द्वारा स्पष्ट आदेश करके कहा था कि दोनों अधिकारी शासकीय सेवा के दौरान क्विभाग की कोई भी डील साईन नहीं करेंगे तथा इस आदेश के परिपालन में तत्कालीन एसडीओ फारेस्ट को सेवा से पृथक कर दिया गया परन्तु श्रीनिवास शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण है ।	प्रश्नांश "क" के क्रम में प्रश्नांश "ख" में चाही गई जानकारी इस कार्यालय की निरक है ।
(ग)	वर्ष 1999 में काले पत्थर के उत्खनन में प्राइवेट कम्पनी को जो लीज स्वीकृत की थी उस कम्पनी पर कोई कार्यवाही हुई यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो उक्त खदान की नपाई कर शासकीय राजस्व की हानि की भरपाई करायेगी ।	प्रश्नांश "क" के क्रम में जानकारी निरक है ।
(घ)	वर्तमान सड़क निर्माण में अवैध खदानों से मुरम जो का उत्खनन किया जा रहा है तो शासन को कितनी राजस्व की हानि हुई ? तो इसकी भरपाई कब और किन फर्मों से की जा रही है ? दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?	वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक कुल 04 प्रकरण अवैध मुरम उत्खनन के दर्ज किये जाकर अर्थदण्ड की राशि 399750/- जमा कराई गई है, राज्य सरकार की सड़क निर्माण कार्यों हेतु मुरम पर रायल्टी देय नहीं है । अतः प्रश्न के संबंध में शेष जानकारी निरक है ।


 खनिज अधिकारी,
 वास्ते-कलेक्टर, दमोह